



संपादकीय

देश की जरूरत, समान नागरिक संहिता

अब वह समय आ गया है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। एक लम्बे अरसे से देश की जनता को इसकी जरूरत महसूस हो रही है। एक देश दो कानून वैसे भी लोकतंत्र के खिलाफ है समान नागरिक संहिता के खिलाफ दुष्प्रचार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आम लोगों को इसका भान नहीं है कि उसमें क्या और कैसे प्रविधान होंगे? इसे देखते हुए उचित यह होगा कि विधि आयोग लोगों के सुझाव प्राप्त कर यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता का कोई मसौद देश की जनता के विचारार्थ पेश करे। इससे ही समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर लगाम लगेगी विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता पर लोगों से सुझाव मांगने के बाद भोपाल के एक सभा में प्रधानमंत्री का यह कहना उल्लेखनीय है कि यह संहिता समय की मांग है। इसका अर्थ है कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। यह अच्छा हुआ कि उहोंने इसका उल्लेख किया कि कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यह काम वास्तव में हो रहा है। अनेक राजनीतिक दल और कुछ सामाजिक-धार्मिक संगठन जिस तरह समान नागरिक संहिता के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, वह शुभ सकें नहीं। समान नागरिक संहिता के खिलाफ उठ रहा आवाजें न कवल संविधान निमार्ताओं के सपनों के विरुद्ध हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने वाली भी हैं। इसके अतिरिक्त ये एक देश में दो विधान की स्थिति बनाए रखने वाली भी हैं विश्व के किसी भी पंथनिरपेक्ष देश में अलग-अलग निजी कानून नहीं हैं, लेकिन भारत में वे इसके बाद भी बने हुए हैं कि संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में यह लिखा गया है कि राज्य देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाएगा। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदुओं के निर्जन कानूनों को तो संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही संहिताबद्ध कर दिया गया, लेकिन अन्य समुदायों के निजी कानून बने रहने दिए गए निःसंदेह ऐसा वोट बैंक की स्तरी राजनीति के कारण किया गया। इसके कोई मतलब नहीं कि सात दशक बाद भी अलग-अलग समुदाय भिन्न-भिन्न निजी कानूनों के जरिये संचालित होते रहें और वे भी तब, जब उनके कारण महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा होती हो और वे अन्याय का शिकार बनती हों। समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है, इसका पता इससे चलता है कि कुछ राजनीतिक दल यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि इससे विभिन्न समुदायों की धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप होगा यह निरा झूट है। समान नागरिक संहिता से किसी समुदाय की धार्मिक रीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला। वह तो केवल सामाजिक कुरीयों को दूर करने में

सहायक होगा। जेस बाल विवाह, ताल तलाक का कुप्रथा खत्म करने की जरूरत थी, वैसे ही उन कुरीतियों को भी खत्म किया जाना चाहिए जिनके कारण महिला अधिकारों का हनन होता है। वास्तव में इसके कारण कई बार विभिन्न उच्च न्यायालय और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जता चुका है समान नागरिक संहिता के खिलाफ दुष्प्रचार इसीलिए किया जा रहा है। क्योंकि आम लोगों को इसका भान नहीं है कि उसमें क्या और कैसे प्रविधान होंगे? इसे देखते हुए उचित यह होगा कि विधि आयोग लोगों के सुझाव प्राप्त कर यथाशङ्ख समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा देश की जनता के विचारार्थ पेश करे। इससे ही समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर लगाम लगेगी समान नागरिक संहिता के मामले में यदि विषयी दलों के साथ-साथ कांग्रेस के पास कहने के कुछ हैं तो केवल यही कि आखिर उसकी पहल इसी समय क्यों की जारी रही है? यह कुछ वैसा ही कुतर्क है जैसा अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया गया था। तब यह कहा गया था कि इस मामले के सुनवाई आम चुनाव के बाद की जानी चाहिए। कुछ विषयी दलों ने समान नागरिक संहिता पर जिस तरह सकारात्मक और तार्किक रवैया अपना लिया है, उससे कांग्रेस की दुविधा बढ़ जाना स्वाभाविक है। कांग्रेस विषयी नेताओं के साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता समान नागरिक संहिता को समय की मांग बता रहे हैं। कांग्रेस को बोट बैंक की सस्ती राजनीति के कारण वैसी कोई भूल करने से बचना चाहिए, जैसी उसने शाहबानों का मामले में की थी। इसकी कीमत केवल उसे ही नहीं, देश को भी चुकाना पड़ी थिं शाहबानों मामले में राजीव गांधी की सरकार कठुरपंथी तत्व के आगे झुकने के बजाय संविधानसम्पत्ति फैसला करती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी होती तो आज स्थिति दूसरी होती। समान नागरिक संहिता का निर्माण लंबित रहना एक तरह से संविधान निर्माताओं के सपनों को जानबूझकर न पूरा करना है। कांग्रेस को इसके अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने तमाम विरोध के बाद भी हिंदू कोड बिल के मामले में किस तरह दृढ़ रवैया अपनाया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है समान नागरिक संहिता संविधान में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित हो समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद वे हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू किया गया है न्दपवितउ ब्यअपस ब्कम का अर्थ स्पष्ट है सभी नागरिकों के लिए एक कानून। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इस कोड वे तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है। यानी की धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। भारत में अभी सिर्फ एक राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वह राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारतीय राज्यों को देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करने को कहा गया है जो पैरे देश में लागू होता हो।

महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी कुछ बड़ा होने वाला है !

अशोक

महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उथल - पृथ्वे के बाद के बाद लगता है कि बिहार में भी कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि जॉब के लिए जमीन घोटाले मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। साल 2017 में भी जब सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पती राबड़ी देवी और तत्कालीन डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उस वक्त भी तेजी से राजनीतिक परिस्थितियां बदली थीं। एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।



खिलाफ हो या अपने मात्रियों के विरुद्ध यहो कारण है कि वर्ष 2017 में जब सीबीआई ने रेलवे होटल टेंडर मामले में तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था तो उन्होंने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा था। नीतीश कुमार का तब भी यह कहना था कि सारी बारें जनता के डोमेन में आनी चाहिए लेकिन जब तजस्वी यादव सभी सवालों का जवाब बिन्दुवार देने में असमर्थ रहे तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से नाता तोड़ कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार में सीबीआई और ईडी की सक्रियता अचानक बढ़ गई थी। इसे लेकर खुद तेजस्वी यादव ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि पुराने मामलों में उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दखिल हो सकता है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं भाजपा की यह सुनियोजित योजना तो नहीं है। हाल ही में हुई राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सांसद सुशील मोदी के बीच हुई मुलाकात को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना

तरह परिचित हैं। लेकिन भाजपा यहां आसानी बॉक ओवर दे देगी यह भी मानना बड़ी भूल है। भाजपा ने पूरा ध्यान हिंदी पट्टी के इस बड़े राज्य पर केंद्रित कर दिया है क्योंकि इस राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी ने मिलकर 39 सीटें जीत ली थीं लेकिन अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी और जड़ीय कुल वोट बैंक भाजपा से बहुत ज्यादा है। एक तरफ लालू यादव के परिवार पर चार्जशीट दाखिल होने की हलचल के बीच दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार की रैली कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो चंपारण के चनपटिया गढ़ थे और उसके बाद लखीसराय गए। शाह का दौरा पिछले हफ्ते पटना में 15 विपक्षी दलों के 32 नेताओं की बैठक के बाद हुआ। शाह की रैली में बिहार भाजपा अध्यक्ष सप्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित राज्य में पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद थे। लखीसराय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है जिसका प्रतिनिधित्व जड़ीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करते हैं।

पार्श्वी दलों में अपरिवार्ता ने नीतीश चाहा

सभा दारा म अमित शाह न नातीश कुमार पर जमकर हमला करते रहे। ऐसे मैं ये सवाल उठने लगा है कि कहीं भाजपा की नजर नीतीश कुमार पर तो नहीं है या फिर महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बिसात बिछाए जाने की तैयारी है। दरअसल विपक्षी एकता के लिए कवायद नीतीश कुमार के साथ ही शरद पवार भी कर रहे थे। भाजपा ने महाराष्ट्र में एनसीपी को तगड़ा झटका दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद शरद पवार कमज़ोर हो गए हैं लेकिन अभी नीतीश कुमार की ओर से चुनावी बरकरार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जून का लखीसराय दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें 'पलटू बाबू' करार दिया, उन्होंने कहा कि नीतीश लालू प्रसाद की आंखों में धूल झोंक हागा। वा नाताशा का पाठी का ताड़ना चाह रही है, भाजपा का मकसद नीतीश की पाटी को तोड़ कर विपक्षी एकता को कमज़ोर करना है। कुछ जानकारों ने बताया कि भाजपा ने राजनीति के लिए कुछ मॉडल बनाए हैं, जिसमें से एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाजपा लोकसभा 2024 से पहले इसी का इस्तेमाल कर रही है। समान नागरिक सहित इसी का एक उदाहरण है। जिन राज्यों में इस कानून की मुखालफत की जा रही है भाजपा पहले इन्हीं राज्यों को टारगेट कर रही है। भाजपा एनसीपी के मॉडल को नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी तरह जेडीयू भी भाजपा के निशाने पर है। लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा बिहार में नीतीश को अप्रसारित बनाना चाहती है।

विपक्षी एकता को झटका

लालत गग

पव २०२४ का युगांधि से यूप भारतीय राजनीति के अनेक गुणा-भाग और जोड़-तोड़ ऐसे दृश्य उभेरे। महाराष्ट्र में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। वहां जो हुआ है उससे विषय में खलबली है, घबराहट एवं बेचैनी स्पष्ट देखी जा सकती है, जो पटकथा महाराष्ट्र में लिखी गयी है, वही बिहार में भी लिखी जा सकती है। राजनीतिक दलों के प्रायचार को दबाने के लिये, सत्ताकांश एवं आंतरिक असंतोष के चलते ऐसे समझौते, दलबदल एवं उल्टी गिनतियां अब आम बात हो गयी है। कल तक सत्ता पक्ष को कौसे वाले अजित पवार अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से बगावत कर डिल्टी सीएम बन गए हैं। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की पार्टी का यह हम्रा आश्वयकारी ही नहीं, बल्कि एक बड़ा विरोधाभास एवं विपक्षी एकता का संकट भी है। एक तरफ इस तरह के घटनाक्रम को राजनीतिक दलों में आंतरिक असंतोष व गुटबाजी से जोड़ा जा सकता है तो दूसरी तरफ सत्ता के उस स्वाद की आकांक्षा से भी, जिसे हर कोई पाना चाहता है। राजनीतिक दलों में बगावत का ऐसा दौर जब भी होता है इस बात को जोर-शोर से प्रचारित किया जाता है कि उनके दल में लोकतंत्र नहीं रहा इसलिए वे अपने विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं। बड़ा प्रश्न है कि इस तरह राजनीतिक दलों से लोकतंत्र गायब होता रहा है, तो ऐसे अलोकतात्त्विक दल कैसे देश के लोकतंत्र को हांक सकें? आजकल राजनीति में उल्टी गिनती एक हस्तक्ख बन गई है, ह्वकिसी महत्वपूर्ण राजनीतिक ऊटापटक या घटनाक्रम की शुरूआत के लिएहै। विभिन्न राजनीतिक दलों में ऐसी कई उल्टी गिनतियां चल रही हैं। कई कद्दावर नेताओं के सार्वजनिक/भावी जीवन की उल्टी गिनतियां चल रही हैं। करोड़ों-अरबों के घोटाले और रोज कोई न कोई उसमें

रणणम् बाद उद्धव ठाकर न धोखा दिया था। सींसी कारण एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत नर सीएम बनने में कामयाब हुए। दरअसल हाराष्ट्र में राकांपा के साथ जो कुछ भी हुआ सका एक बड़ा कारण यह भी है कि शरद वार चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के साथ उत्तरकार बनने को राजी होकर भी तीन-चार दिनों ही उन्हें पलटी मार ली थी। इस तरह से शरद पवार ने भी अमित शाह को धोखा दिया था। एक चीज साफ नजर आती है कि भाजपा ने धोखा देने वाले नेता अथवा पार्टी को अमित शाह राजनीतिक रूप से माफ नहीं करते। अमित शाह उस नेता या पार्टी को राजनीतिक सबक में खाने के लिए, बस सही समय का इंतजार नहीं है।

ज्ञानघनाक्रम के लिए विपक्षी दल भाजपा को नज़मेदार ठहरा रहे हैं, भाजपा इसे राकांपा का अन्दरूनी मामला बता रही है तो एनसीपी के बारी ताता किसी दबाव से इनकार करते हुए विकास पाटेल लिए शिंदे सरकार का साथ देने की बात कह रहे हैं। राजनीतिक जोड़-तोड़ के माहिर खिलाड़ी हैं राकांपा प्रमुख शरद पवार के लिए यह अश्चित ही बड़ी राजनीतिक मात साबित हुई है। इसमें वक्त में जब समूचे भारतीय राजनीति में वार खुद विपक्षी एकता के प्रयासों में जुटे थे, नक्ती ही पार्टी में यह विभाजन महाराष्ट्र की नई राजनीतिक इवारत लिखने वाला होगा, इसमें जोई संशय नहीं है। लेकिन अहम सवाल यही ठिठा है कि देश की राजनीति आखिर सत्ता की गतिर ऐसे रास्ते पर क्यों चलने लगी है? पृथक नानव चिंह पर जीत कर आने वाले आसानी से प्रयोगियों से हाथ क्यों मिलाने लगे हैं? देखा जाए तो धनबल के सहरे सत्ता पाना और सत्ता 5 सहरे धनबल हासिल करना आज की जननीति की विकृति एवं विसंगति बन गया है। हाराष्ट्र में राकांपा के अंदर मची उठापटक के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में जनता दल युनाइटेड और झारखण्ड में झारखण्ड किंतु मोर्चा का पार्टी में टूट का खतरा सताने लगा

हा एस हा डर कुछ आर छाटा पाटा का भा है। लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट जनता दल युनाइटेड खेमे में देखी जा रही है। जनता दल युनाइटेड की यह घबराहट स्वाभाविक भी है क्योंकि उसने भाजपा को जो धोखा दिया था उसका जवाब अब तक भाजपा ने नहीं दिया है। इन विपक्षी दलों की यह घबराहट सत्ता-लोलुपता की प्रवृत्ति के साथ किये गये प्रश्नाचार के कारण है। शायद यही बजर है कि विपक्षी पार्टियों की बैंगलुरु में प्रस्तावित बैठक टलने की चर्चा भी शुरू हो गयी, लेकिन कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि बैठक बैंगलुरु में ही 17 और 18 जुलाई को ही होगी। कांग्रेस नेताओं ने यह बताना भी जरूरी समझा कि महाराष्ट्र में हुई घटनाओं का विपक्षी दलों के एकता के प्रयासों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मगर पार्टी में सेंध लगने के बाद इन दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजनीतिक धरातल को बनाए रखने का है। सवाल यह खड़ा हुआ है कि क्या नेताओं के साथ-साथ पार्टी का वोट आधार भी दूसरे खेमे में चला गया है। विपक्षी दलों की एकता से पहले ही उनके बिखरने की घटनाएं आश्वर्यकारी होने के साथ ही राजनीतिक दलों के कमज़ोर मनोबल की परिचायक है एक और बड़ा प्रश्न है कि भारतीय राजनीति की शुचिता एवं आदर्श की रक्षा कैसे हो पायेगी? क्योंकि उभर रही सबसे बड़ी विडम्बना एवं विसंगति यही है कि जनता जिसको सत्ता से बाहर रखना चाहती है वह ऐसे अनचाहे घटनाक्रम से सत्ता हथिया लेता है। दलबदल कानून की धज्जियां उड़ी हुई देखकर भी अदालतों से लेकर चुनाव आयोग तक ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। चुनाव बाद होने वाले गठबंधनों में सत्ता-लोलुपत की प्रवृत्ति तब ही रुकेगी जब सवैधानिक प्रावधानों में जरूरी बदलाव हों। गैर लोकतात्त्विक गठबंधनों को रोकने के लिये राजनीतिक दलों को सशक्त आचार-पर्वता से बांधना भी जरूरी है। भारत की जनता को भी राजनीतिक श्रेष्ठ की लम्जे समय से प्रतीक्षा है।

फ्रांस को नस्लीय भेदभाव खत्म करने की आवश्यकता !

सुनील कुमार महला

धर्म और इस्लाम से जुड़ी नस्लों के प्रति पूर्वाग्रह का एक लंबा इतिहास रहा है और कुछ लोग इस घटना को नस्लवाद के चश्मे से देख रहे हैं, जो कि ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। किशोर की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी यह बात कही है कि प्रांस को अपनी पुलिस में नस्लीय भेदभाव के गहरे मुद्दों का समाधान करना चाहिए उल्लेखनीय है कि अर्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर की पुलिस की गोली से हुए मौत के बाद पूरे देश में भड़की हिंसा की आग थमी नहीं है।

सच तो यह है कि इस हिंसा ने पूरे प्रांस को हिलाकर रख दिया है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। वास्तव में, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए जल्द से जल्द हिंसा पर लगाम लगनी चाहिए समस्या का समाधान जोर जबरदस्ती या पुलिसिया कार्रवाई से भी नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को सौहार्दपूर्ण तरीके अपनाकर प्रांस में हो रही हिंसा पर लगाम लगाने की जरूरत

सब के लिए हितकारी है सामान नागरिक संहिता

विवक्त रजन श्रावास्तव

भारतीय संविधान विश्व के चुनिंदा आदर्श डायकूमेंट्स में से एक है। हमारे संविधान निमाताओं ने बड़े सोच विचार के उपरान्त इसमें यह प्रावधान तो किया कि हमें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाना है, किन्तु अन्य कई मामलों जैसे राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी, आशक्षण, काश्मीरी या पूर्वोत्तर के मसलां पर लचीली व्यवस्थाओं के अंतर्गत बउत को भी तुरंत अपनाया नहीं गया और न ही इसके लिये भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। परिणाम यह हुये कि बोट की तुष्टीकरण की राजनीति ने अपने पैर पासर लिये और विविधता का हवाला देकर इस अति आवश्यक कार्य को सरकारों द्वारा लगातार टाला जाता रहा। पहले जब पार्टी बृहपत्र की मरकूरें थीं तो उन्हें सरकारें बनी तब तो इसे लागू करना वैधानिक तरीके से संभव ही नहीं था। अब जब वी जे पी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तब भी अन्य मुद्दों की प्राथमिकता के चलते अब तक यह लागू नहीं किया गया है। अब जब देश में समन्वय, समरसता के लिये इसे लागू करने के प्रयास शुरू हुये हैं तो एक पौंडिंग बड़े कार्य को बहुमत के समर्थन के बाद भी विरोधी दलों में से कोई इसे ध्वनीकरण का बहाना कह रहा है तो कोई इसे जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने की सलाह देता है। कुछ कट्टर पथियों में बेवजह एक आदर्श व्यवस्था में उनकी जड़ता की बजह से खतरा लग रहा है। फिलहाल समान नागरिक सहित भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लगा करने का स्थिति यह है कि धर्मनिरपेक्ष होते हुये भी हमारे देश में विभिन्न धार्मिक नियमों के अनुसार कुछ धर्मों के लोग संचालित हो रहे हैं। देश में समान नागरिक सहित लागू हो जाने पर सच्चे अर्थों में भारत में धर्म निरपेक्षता लागू हो सकी जब सभी नागरिकों के साथ हर स्थिति में समान कानूनी व्यवहार होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अतः कानूनी रूप से सभी नागरिकों पर समान नियम लागू हो जाने से धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी तरह का कोई डर बेवजह है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व और

चित्रकूट - उन्नाव संदेश

राजकीय बालिका इंटर कालेज में हैं सभी सुविधायें

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। राजकीय बालिका इंटर कालेज कर्वी की प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्णा वर्मा ने बताया कि राजकीय बालिका इंटर कालेज कर्वी में शिक्षण कार्य कक्ष 12 तक चल रहा है। लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकाएं कार्यरत हैं। मानविकी वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत झीताहास, नारायणीक शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, कंप्यूटर एवं वैज्ञानिक वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा व्यवसायिक वर्ग के विषय परिषान, रचना एवं सज्जा, फैशन डिजाइनिंग के साथ प्रैवीग योजना के तहत ब्लैटी एंड वैलनेस रिटेल मार्केटिंग का भी अध्ययन कार्य कराया जाता है।

मंगलवार को उन्होंने बताया कि सभी विषय रोचक एवं पूर्ण मनोयोग से पढ़ाया जाते हैं। विद्यालय की परीक्षा फल प्रतिव्रत्त प्रतीति कर रहा है। बोर्ड परीक्षा अच्छे आ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022-23 में हाईस्कूल का 94.50 और इंटरमीडिएट का 86.6 प्रैसडी रहा है। प्रदेश में हाईस्कूल की छात्र प्रियासी सिंह का 90 प्रतिशत एवं इंटर में प्रिया सिंह का 89.6 प्रतिशत था। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतिवेशितायें भी होती हैं। बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। स्पोर्ट्स में बच्चे हिस्सा लेते हैं। विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।

शासनादेशों का उल्लंघन कर रहे

डॉक्टर

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिले के सीएचसी व पीएचसी में तैनात डॉक्टर अंगद की तरह पैर जाए हैं। शासनादेश है कि डॉक्टर को पांच वर्ष बाद जिले तथा अठ वर्ष बाद मंडल स्तर पर तबादला किया जाए। जिले में तमाम डॉक्टर ऐसे हैं जो लिपिक से मिलियपत कर सूची में अपना नाम न भेजते हैं।

मंगलवार को डॉक्टरों के जिले में जमे होने की खबर मिली। डॉक्टर खुद सीएचसी में जमे हैं। मंडल स्थानांतरण को ऐसे डॉक्टरों की सूची भेजी गई है जो पहले से ही पीजी करने चले गए हैं। सीएचसी में पैर जाए डॉक्टर के तीर पर लखन स्वरूप गर्म, डॉ शेलेंट्री सिंह, डा शेखर वैश्य, डा राजेश सिंह आदि अन्य डॉक्टर जिले में आठ साल से जमे हैं।

ऐसे डॉक्टरों का तबादला जिला स्तर पर मंडल स्तर पर नहीं हो रहा है। अखिर किसकी मेहरबानी से शासनादेशों का डॉक्टर उल्लंघन कर रहे हैं।

दस तक करें आवेदन

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने तीन जुलाई के निर्देश के क्रम में नोडल प्रधानाचार्य राजकीय आयोगिक प्रशिक्षण संस्थान मनिकपुर मनरिंद में बताया कि प्रवेश सत्र अगस्त को आवेदन की अन्तिम तिथि दस जुलाई रात 12 बजे तक बढ़ा दी गयी है। इच्छुक अधिकारियों से कहा कि आवेदन परिषद की वेबसाइट पर आवेदन नियारित तिथि तक कर सकते हैं।

छह को होगी भवन मानचित्र बैठक

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सचिव वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के तहत मंजूरी को प्राप्त भवन मानचित्रों के जल्द नियारण को प्राधिकरण ने मानचित्र समाधान दिवस छह जुलाई को सवेरे दस से अपराह्न 10 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में होगा। मंगलवार में उन्होंने बताया कि संबंधित भवन मानचित्र प्रस्तुतकर्ता संबंधित विभाग एवं अनुसार भवन की आपत्तियों का तत्काल निस्तारण कर भवन मानचित्र मंजूरी की कार्यवाही की जायेगी। सभी संबंधित छह जुलाई को सम्पूर्ण से पहुंचकर सुविधा का उपयोग करेंगी।

वेबसाइट पर लोड करें क्लेम बिल

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। राजकीय बालिका इंटर कालेज कर्वी की प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्णा वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित काट्रवृत्ति परिषाक्षण-एसएमएस 2023-24 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के प्रमाण पत्र जनपदीय नोडल विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कालेज के कार्यालय से प्राप्त करें। प्रमाण पत्र के आधार पर ही क्लेम बिल डाटा अपलोड होगा। 2022-23, 2021-22 एवं 2020-21 में सफल छात्रवृत्ति के नवीनीकरण को लाभार्थी संबंधित वेबसाइट पर क्लेम बिल डाटा अपलोड कर सकते हैं।

मोपेड पे सवार पति पत्नी को हाइवा ट्रक ने रौंदा, मौत

बाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के लौटीबीर पुलिया के समीप हाईवे पर सोमवार की दोपहर में पति से साथ मोपेड से जा रही रीता (35) की हाइवा ट्रक की चीपेट में आने से मौत हो गई। उसका पति उमा बच गया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार जंसा क्षेत्र के कुंडरिया गांव का उमा पती रीता के साथ रोहनी क्षेत्र की चीपेट में आने से मौत हो गई। उसका पति उमा बच गया। इसी दौरान हाईवे पर पीछे से आ रहे थे मोपेड में टक्कर मार दी। इसके बाद दम्पती मोपेड समेत अनियन्त्रित होकर गिरे पर्सी सड़क पर और पति उमा किनारे गिरा। इनमें हाइवा ने रीता को रौंद दिया। दुर्घटना देख शोर मचाते लोग दौड़े चालक मौके पर हाइवा ओडिकर भाग निकला। सूचना पर हुए चीपेट के पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पुलिस ने हाइवा को कब्जे में ले लिया है।

यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद के दो सदस्यों को पकड़ा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश आतंकवाद नियोगिक दस्ते (एटीएस) ने खुफिया एजेंसियों से मिले इन्हुंने के बाद अल-कायदा की सहायक इकाई आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) के दो सदस्यों को गिरफ्तर किया है।

पिपलता किए गए लोगों की पहचान 38 वर्षीय सदाम शेख और 23 वर्षीय जिजान खान के रूप में की गई है।

विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, प्रशासन कुमार ने कहा कि गोंडा का मूल निवासी सदाम बेंगलुरु में एसटीसी नामक कंपनी में डाइवर के रूप में काम करता था।

कुमार ने कहा, "सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक नियारानी के दौरान, यह सामने आया है कि सदाम शेख कट्टरपथी था और पाकिस्तान में आतंकवादियों के संपर्क में था।"

सदाम ने यह भी कहा कि ओसामा बिन लादेन, जाकिर मसा, रियाज नाइकू, नावेद जदू, समीर टाइगर जैसे आतंकवादी उसके आदर्श थे और उसके फौन में इन आतंकवादियों से संबंधित तस्वीरें और विडियो भी बरामद हुए हैं।

दुसरा आरोग्य जम्मू-कश्मीर के पुंछ का रहने वाला रिजिवान खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद का प्रचार कर रहा था। वह फिलहाल बिहार में सियायरेंटी गाँव की नौकरी कर रहा है।

दूसरे दिन प्रभारी मंत्री ने देखे जिले के विकास कार्य -मंत्री ने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के दिये निर्देश- अपात्रों को घर देने की डीएम से की जांच की मांग

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। सुधे के राज्य मंत्री स्थान्त्रिम प्रधारी पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग विभाग विभाग-जिला प्रभारी मंत्री ने देंद्र के दूसरे दिन कई परियोजनाओं का स्थानीय निरीक्षण किया। मानिकपुर ब्लाक के बौद्ध चौपड़ा के परियोजना तालाब को बहार घर तल नल योजना का समय से कार्य पूरा हो गया है। डीसी योजना गंधीजी निरीक्षण दिव्यांग विभाग के बैठक के बाद जिले के विभिन्न कार्यों को गुन्तु बोडी के द्वारा देखा जाएगा। डीसी योजना गंधीजी निरीक्षण दिव्यांग विभाग के बैठक के बाद जिले के विभिन्न कार्यों को गुन्तु बोडी के द्वारा देखा जाएगा।

एवरपोर्ट में टीमिंग लिलिंग, अपोच रोड, बाउंडी वॉल, एवरपोर्ट के छोटे दिव्यांग विभाग विभाग देखा जाएगा। डीसी योजना गंधीजी निरीक्षण दिव्यांग विभाग के बैठक के बाद जिले के विभिन्न कार्यों को गुन्तु बोडी के द्वारा देखा जाएगा।

एवरपोर्ट में टीमिंग लिलिंग, अपोच रोड, बाउंडी वॉल, एवरपोर्ट के छोटे दिव्यांग विभाग विभाग देखा जाएगा। डीसी योजना गंधीजी निरीक्षण दिव्यांग विभाग के बैठक के बाद जिले के विभिन्न कार्यों को गुन्तु बोडी के द्वारा देखा जाएगा।

एवरपोर्ट में टीमिंग लिलिंग, अपोच रोड, बाउंडी वॉल, एवरपोर्ट के छोटे दिव्यांग विभाग विभाग देखा जाएगा। डीसी योजना गंधीजी निरीक्षण दिव्यांग विभाग के बैठक के बाद जिले के विभिन्न कार्यों को गुन्तु बोडी के द्वारा देखा जाएगा।

एवरपोर्ट में टीमिंग लिलिंग, अपोच रोड, बाउंडी वॉल, एवरपोर्ट के छोटे दिव्यांग विभाग विभाग देखा जाएगा। डीसी योजना गंधीजी निरीक्षण दिव्यांग विभाग के बैठक के बाद जिले के विभिन्न कार्यों को गुन्तु बोडी के द्वारा देखा जाएगा।

एवरपोर्ट में टीमिंग लिलिंग, अपोच रोड, बाउंडी वॉल, एवरपोर्ट के छोटे दिव्यांग विभाग विभाग देखा जाएगा। डीसी योजना गंधीजी निरीक्षण दिव्यांग विभाग के बैठक के बाद जिले के विभिन्न कार्यों को गुन्तु बोडी के द्वारा देखा जाएगा।</

